



Daily करेंट अफेयर्स

➤ 26 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. PM मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में 18,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एशिया का सबसे चौड़ा गंगा पुल और कोलकाता मेट्रो विस्तार शामिल।



22 अगस्त 2025 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो राज्यों की यात्रा पर निकले - पहले बिहार के गया और फिर कोलकाता - जहाँ उन्होंने 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढाँचा और सार्वजनिक सेवा विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे कनेक्टिविटी, शहरी गतिशीलता और लोक कल्याण को बल मिला।

- गया में, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग ₹13,000 करोड़ मूल्य की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया—जिनमें एक कैंसर अस्पताल, बिजली संयंत्र और शहरी सुधार शामिल हैं। उन्होंने दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और गंगा पर बने विशाल औटा-सिमरिया छह-लेन केबल-स्टेड पुल का अनावरण किया, जिससे मोकामा, बेगूसराय और पटना के बीच संपर्क बेहतर होगा और चक्कर लगाने की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा कम हो जाएगी।

- औटा-सिमरिया पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर बरौनी-मोकामा छह लेन वाला गंगा पुल कहा जाता है, पहुँच मार्ग (1.86 किमी केबल-स्टेड सेक्शन) सहित 8.15 किमी लंबा है और एशिया का सबसे

चौड़ा पुल है। इस पुल की संरचना में प्रत्येक दिशा में तीन लेन और पैदल पथ हैं, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच निर्बाध आवागमन को सुगम बनाते हैं और एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि का प्रतीक हैं।

- दोपहर में, प्रधानमंत्री मोदी ₹5,200 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करने कोलकाता पहुँचे। उन्होंने कई नए मेट्रो खंडों का उद्घाटन किया और जेसोर रोड से जय हिंद हवाई अड्डे तक मेट्रो का संचालन किया। सियालदह-एस्प्लेनेड और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय कॉरिडोर सहित ये विस्तार मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाएँगे, भीड़भाड़ कम करेंगे और सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करेंगे।

Key Points:-

(i) दोनों राज्यों में कुल विकास मूल्य ₹18,000 करोड़ से अधिक होने के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने एकीकृत बुनियादी ढाँचे को विकास के एक प्रमुख कारक के रूप में रेखांकित किया। इस बहु-राज्यीय यात्रा में सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन उन्नयन के साथ-साथ मज़बूत बुनियादी ढाँचे को भी शामिल किया गया है—जो आसन्न विधानसभा चुनावों के बीच सरकार के "जीवन सुगमता" एजेंडे को और मज़बूत करेगा।

(ii) दोनों ही जगहों पर, प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया और नागरिकों से विकास-केंद्रित शासन का समर्थन करने का आग्रह किया। बिहार में, उन्होंने 'विकसित भारत' और सरकारी योजनाओं के महत्व पर ज़ोर दिया, जबकि बंगाल में, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के सत्तारूढ़ नेतृत्व की आलोचना की और तेज़ी से बढ़ते मेट्रो विस्तार को बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए केंद्रीय समर्थन का प्रमाण बताया।

2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम 2025 और 1 अप्रैल, 2026 से आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करने वाले नए कानून को मंजूरी दी।



अगस्त 2025 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम (i-T अधिनियम), 2025 को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसे बाद में विधि एवं न्याय मंत्रालय (MoLJ) द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया। यह नया कानून 1961 के आयकर अधिनियम का स्थान लेगा और 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

- आयकर अधिनियम, 2025, दशकों पुराने आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर एक आधुनिक और सरलीकृत संस्करण के साथ पेश किया गया है जिसका उद्देश्य जटिलता को कम करना और अनुपालन में सुधार करना है। सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि यह अधिनियम करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने और कर प्रशासन में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

- नए अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह कोई नई कर दर लागू नहीं करता, बल्कि अनावश्यक प्रावधानों और पुराने कानूनी ढाँचों को हटाने पर केंद्रित है। ऐसा करके, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाताओं को कम कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़े और समग्र कराधान प्रक्रिया अधिक सरल हो।

- नए अधिनियम के तहत शुरू किए गए संरचनात्मक सुधारों में आयकर अधिनियम, 1961 में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 करना तथा अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 करना शामिल है। कानून की शब्द संख्या भी 5.12 लाख शब्दों से घटाकर 2.6 लाख शब्द कर दी गई है, जिससे यह अधिक संक्षिप्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो गया है।

Key Points:-

(i) पहली बार, अधिनियम में 39 नई तालिकाएँ और 40 नए सूत्र शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य करदाताओं और पेशेवरों को अधिक स्पष्टता और संदर्भ में आसानी प्रदान करना है। यह आधुनिकीकरण व्यक्तिगत करदाताओं और व्यवसायों, दोनों के लिए कराधान को अधिक सुलभ बनाने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

(ii) आयकर अधिनियम, 2025 द्वारा लाया गया एक बड़ा बदलाव आकलन वर्ष (AY) और वित्तीय वर्ष (FY) का नाम बदलकर "कर वर्ष" करना है। यह बदलाव कर शब्दावली में भ्रम को दूर करने और एकरूपता लाने के लिए किया गया है, जो भारत की कर प्रशासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

3. आंध्र प्रदेश सरकार ने 8,500 रोजगार गारंटी योजना कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर की घोषणा की।



अगस्त 2025 में, आंध्र प्रदेश पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कॉर्पोरेट वेतन पैकेज के साथ साझेदारी की, ताकि 8,500 रोजगार गारंटी योजना कर्मचारियों को 3 लाख से 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जा सके - जो उन्हें और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

- यह ऐतिहासिक निर्णय ग्रामीण विकास में लगे रोजगार गारंटी योजना के कर्मचारियों को आकस्मिक चोट या मृत्यु के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित बीमा राशि ₹3 लाख से ₹10 लाख तक है, जो प्रत्येक लाभार्थी के मुआवजे के स्तर के अनुसार निर्धारित की जाती है।

- यह योजना भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ उसके कॉर्पोरेट वेतन पैकेज के तहत एक समझौते के माध्यम से सक्षम है, जिससे निर्बाध कार्यान्वयन और दावा प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। SBI के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर, सरकार कर्मचारियों के लिए शून्य लागत पर बीमा लाभों तक त्वरित और परेशानी मुक्त पहुँच सुनिश्चित करती है।

Key Points:-

(i) आंध्र प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लगभग 8,500 कर्मचारी इस कवरेज के पात्र हैं। यह महत्वपूर्ण पहुँच, ज़मीनी स्तर के कर्मचारियों, विशेष

रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों, को सुरक्षित रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

(ii) यह नीति मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों के परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करके, यह पहल अचानक विकलांगता या मृत्यु के कारण होने वाले वित्तीय बोझ और भावनात्मक संकट को कम करने में मदद करती है।

(iii) यह उपाय आंध्र प्रदेश में स्थायी सामाजिक सुरक्षा पर उभरते हुए ध्यान का उदाहरण है। यह स्वास्थ्य सेवा योजनाओं और कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों जैसी अन्य सरकारी पहलों का पूरक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में एक सुधारवादी रणनीति को रेखांकित करता है।

4. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने "विकसित त्रिपुरा-2047" विज़न दस्तावेज़ का अनावरण किया।



22 अगस्त, 2025 को, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने प्रज्ञा भवन, अगरतला में "विकसित त्रिपुरा-2047" विज़न दस्तावेज़ का अनावरण किया। यह रोडमैप त्रिपुरा के विकास लक्ष्यों को "विकसित भारत @2047" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित

करता है, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना है।

- इस विज्ञान दस्तावेज़ का विषय "उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा" है, जो समग्र विकास और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

- इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संपर्क के विस्तार के साथ-साथ 100% नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, सार्वभौमिक साक्षरता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

Key Points:-

(i) त्रिपुरा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) पहले ही 14.21% बढ़ चुका है, जिसका अनुमानित लक्ष्य 2047 तक 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

(ii) यह योजना प्रति व्यक्ति आय को मज़बूत करने, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 के अनुरूप सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने पर ज़ोर देती है।

(iii) यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के सहयोग से तैयार किया गया है, जो त्रिपुरा की दीर्घकालिक प्रगति के लिए संरचित विकास पथ सुनिश्चित करता है।

5. महाराष्ट्र ने ब्रिटेन और भारत के साथ व्यापार साझेदारी को मज़बूत करने के लिए जीआईबीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



22 अगस्त, 2025 को, महाराष्ट्र सरकार ने भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया बिज़नेस कॉरिडोर (GIBC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य महाराष्ट्र और यूरोप, विशेष रूप से UK के बीच व्यापार, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देकर सीमा पार व्यापार साझेदारी को मज़बूत करना है। GIBC वैश्विक आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलते हुए एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा।

- इस समझौते के तहत, GIBC UK और यूरोप में महाराष्ट्र के उद्योग विभाग की एक विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करेगा, जिससे निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। मज़बूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में महाराष्ट्र की भूमिका को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Key Points:-

(i) यह साझेदारी बैंकिंग एवं वित्त, बुनियादी ढाँचा, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा (RE), स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे उच्च-संभावना वाले क्षेत्रों

में सहयोग को लक्षित करेगी। इस प्रकार, यह समझौता ज्ञापन वैश्विक व्यवसायों के लिए महाराष्ट्र के साथ सहयोग हेतु निर्बाध जुड़ाव सुनिश्चित करता है।

(ii) यह पहल 2047 तक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में खुद को स्थापित करने के महाराष्ट्र के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है।

(iii) सहयोग के माध्यम से, भारत और UK दोनों का लक्ष्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना, औद्योगिक विकास का समर्थन करना और प्रमुख क्षेत्रों में व्यवसायों और निवेशकों के लिए स्थायी अवसर पैदा करना है।

दोहरी नेतृत्व भूमिका मीडिया कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण विकास में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है।

● 23वें AIBD महासम्मेलन और संबद्ध बैठकों की अध्यक्षता भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गौरव द्विवेदी ने की।

● 2025 के महाधिवेशन का विषय था "लोगों, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया", जो क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए समावेशी और जिम्मेदार मीडिया प्रथाओं पर केंद्रित था।

Key Points:-

INTERNATIONAL

1. थाईलैंड में 23वें आम सम्मेलन में भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया।



भारत को एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (AIBD) के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। 23वें AIBD महासम्मेलन के दौरान सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद भारत को चुना गया है। यह सम्मेलन 19 से 21 अगस्त, 2025 तक थाईलैंड के फुकेत में आयोजित किया गया था।

● AIBD कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत का चुनाव वैश्विक मीडिया सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि देश पहले से ही 2022 से AIBD महासम्मेलन के अध्यक्ष का पद संभाल रहा है। यह

(i) इस कार्यक्रम में 45 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 92 सदस्य संगठनों ने भाग लिया, जिनमें 26 सरकारी सदस्य, 48 राष्ट्रीय प्रसारक और 44 सहयोगी संगठन शामिल थे। एशिया-प्रशांत देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रतिनिधियों ने मीडिया विकास और नीतिगत आदान-प्रदान की रणनीतियों पर चर्चा की।

(ii) एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (AIBD), जिसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) के तत्वावधान में संचालित होता है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है जो प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण के माध्यम से जीवंत, सहयोगी मीडिया वातावरण को बढ़ावा देता है।

(iii) सीमा पार मीडिया सहयोग को बढ़ावा देने में प्रसार भारती की सक्रिय भागीदारी से AIBD में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है। गौरव द्विवेदी के भारत का प्रतिनिधित्व करने से, यह नेतृत्वकारी पद देश को दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने, सार्वजनिक प्रसारकों को सशक्त बनाने और सतत मीडिया प्रथाओं के माध्यम से संतुलित वैश्विक आख्यान को

बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा।

BANKING & FINANCE

1. साउथ इंडियन बैंक ने 'SIB गोल्ड एक्सप्रेस' लॉन्च किया, जो सोने के मूल्य के 90% तक ऋण प्रदान करेगा।



अगस्त 2025 में, साउथ इंडियन बैंक (SIB) ने 'SIB गोल्ड एक्सप्रेस' नाम से अपना नया स्वर्ण ऋण उत्पाद पेश किया, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को उनकी स्वर्ण संपत्तियों के मूल्य का लाभ उठाकर आसान, त्वरित और लचीली ऋण सुविधा प्रदान करना है। यह योजना व्यक्तियों और व्यवसायों, दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

- 'SIB गोल्ड एक्सप्रेस' ग्राहकों को सोने के मूल्यांकित मूल्य के 90% तक का ऋण-से-मूल्य (LTV) अनुपात प्रदान करता है, जो पारंपरिक स्वर्ण ऋण उत्पादों की तुलना में उच्च ऋण पहुंच सुनिश्चित करता है।

- इस योजना के तहत न्यूनतम ऋण राशि 25,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि ग्राहक अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं।

Key Points:-

(i) 'SIB गोल्ड एक्सप्रेस' की पुनर्भुगतान अवधि ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई

है, जिससे उधारकर्ता तीन साल तक की पुनर्भुगतान अवधि चुन सकते हैं। यह लंबी पुनर्भुगतान अवधि उन लोगों के लिए अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है जो व्यक्तिगत खर्चों या व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।

(ii) इस उत्पाद को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के साथ-साथ गैर-एमएसएमई और लघु व्यवसाय संचालकों पर मुख्य रूप से केंद्रित करके पेश किया गया है। सुरक्षित स्वर्ण-आधारित ऋण प्रदान करके, इस पहल से उद्यमियों को कार्यशील पूंजी, विस्तार परियोजनाओं और अन्य व्यवसाय-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

(iii) इसके अतिरिक्त, 'SIB गोल्ड एक्सप्रेस' को व्यक्तिगत उपक्रमों या वित्तीय आपात स्थितियों के लिए ऋण सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। अपनी सरल दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया, त्वरित संवितरण और उच्च LTV अनुपात के साथ, यह उत्पाद ग्राहक-केंद्रित वित्तीय समाधान प्रदान करने की साउथ इंडियन बैंक की प्रतिबद्धता को और मज़बूत करता है।

2. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी (USGIC) ने सूचना सुरक्षा के लिए ISO 27001:2022 और व्यावसायिक निरंतरता के लिए ISO 22301:2019 प्राप्त किया।



अगस्त 2025 में, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (USGIC) ने दो प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की—सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (ISMS) के लिए ISO 27001:2022 और व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन प्रणालियों (BCMS) के लिए ISO 22301:2019। ये मान्यताएँ इसकी वैश्विक विश्वसनीयता को बढ़ाती हैं और ग्राहकों के विश्वास को मज़बूत करती हैं।

- यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ISO 27001:2022 प्राप्त होना संवेदनशील डेटा, बौद्धिक संपदा और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- यह प्रमाणन विश्व स्तर पर सूचना सुरक्षा मानकों में सर्वोच्च मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो डेटा उल्लंघनों और साइबर जोखिमों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- ISO 22301:2019 प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि USGIC ने एक सुदृढ़ व्यावसायिक निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (BCMS) स्थापित की है, जो परिचालन संबंधी व्यवधानों से निपटने के लिए तत्परता सुनिश्चित करती है। यह मान्यता आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों को पुनः प्राप्त करने और बनाए रखने की कंपनी की क्षमता को प्रमाणित करती है।

Key Points:-

(i) इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करके, USGIC ने प्राकृतिक आपदाओं, साइबर हमलों या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तत्परता प्रदर्शित की है। इससे पॉलिसीधारकों को निर्बाध सेवाएँ सुनिश्चित होती हैं, जिससे कंपनी की परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता में विश्वास और भी मज़बूत होता है।

(ii) ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएँ USGIC को प्रतिस्पर्धी बीमा परिदृश्य में एक दूरदर्शी और विश्वसनीय बीमाकर्ता के रूप में स्थापित करती हैं। ये मान्यताएँ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और तेज़ी से गतिशील बाज़ार परिवेश में ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने की कंपनी की रणनीति के अनुरूप हैं।

(iii) यह उपलब्धि भारत में अग्रणी बीमा कंपनियों में USGIC की स्थिति को और भी पुख्ता करती है, क्योंकि यह इस क्षेत्र की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक बन गई है जिन्हें एक साथ ISO 27001:2022 और ISO 22301:2019 दोनों प्राप्त हुए हैं। यह न केवल इसकी वैश्विक छवि को मज़बूत करता है, बल्कि नवाचार-संचालित, ग्राहक-केंद्रित प्रथाओं को अपनाने के इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

3. इंडसइंड बैंक और एनएसआईसी ने एमएसएमई के लिए ऋण पहुँच मजबूत करने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए

IndusInd Bank

अगस्त 2025 में, इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) के तहत एक मिनी रत्न कंपनी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (NSIC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, ताकि भारत भर में MSMEs के लिए ऋण पहुंच को बढ़ाया और विस्तारित किया जा सके।

- यह MoU केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी (MoMSME), सुभाष चंद्र लाल दास (सचिव, MoMSME), मर्सी एपाओ (संयुक्त सचिव, MoMSME) और डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, NSIC) की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ। इनकी भागीदारी ने संरचित वित्तीय समाधानों के माध्यम से MSMEs को सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस को उजागर किया।

- सहयोग का उद्देश्य संस्थागत ऋण वितरण में तेजी लाना और 6.7 करोड़ से अधिक उद्यम-पंजीकृत MSMEs को व्यापक वित्तीय और डिजिटल समाधान प्रदान करना है।

- NSIC के स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र और इंडसइंड बैंक के मजबूत वित्तीय आधार का लाभ उठाकर, साझेदारी का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों के सामने आने वाले वित्तपोषण अंतर को पाटना है।

Key Points:-

(i) इस समझौता ज्ञापन के तहत इंडसइंड बैंक अनुकूलित बैंकिंग उत्पाद प्रदान करेगा, जिनमें

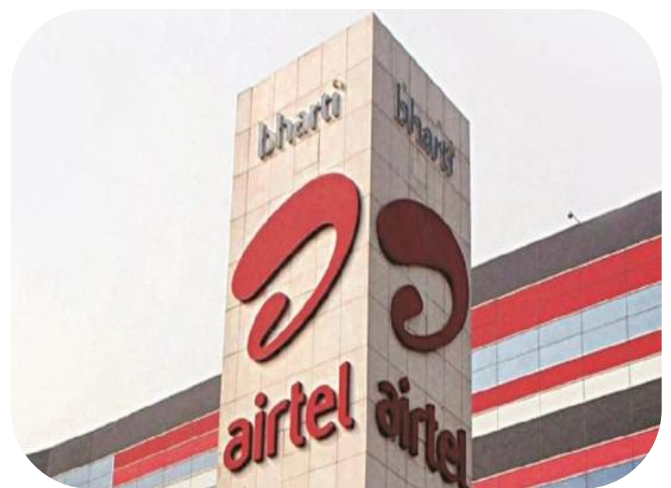
कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण, संरचित ऋण सुविधाएँ और व्यापार वित्त समाधान शामिल हैं। ये पेशकशें तरलता को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं कि MSMEs अपनी परिचालन और विस्तार संबंधी ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

(ii) यह साझेदारी NSIC की प्रमुख योजनाओं जैसे क्रेडिट सुविधा योजना (CFS) को भी समर्थन देती है, जो MSMEs को संस्थागत वित्त तक पहुंच प्रदान करती है, और एकल बिंदु पंजीकरण योजना (SPRS), जो सरकारी खरीद में वरीयता सुनिश्चित करती है।

(iii) इस संरेखण से पूरे भारत में MSMEs के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता, बाजार पहुंच और दीर्घकालिक विकास के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

MOUs and Agreement

1. भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारती एयरटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



अगस्त 2025 में, भारतीय सेना के दाओ डिवीजन ने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी और अंजॉ जिलों के अग्रिम इलाकों में डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारती एयरटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह

सहयोग दूरसंचार अवसंरचना में सुधार, सुरक्षा बलों को सहयोग और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

- इस समझौता ज्ञापन पर अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती गाँवों और दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से हस्ताक्षर किए गए। यह पहल न केवल इन क्षेत्रों के निवासियों, बल्कि अग्रिम क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के जवानों को भी विश्वसनीय संचार सुविधाएँ प्रदान करेगी, जिससे चुनौतीपूर्ण स्थानों पर बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

- यह समझौता सीमावर्ती ज़िलों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार करके डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से, यह पहल सुरक्षा बलों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम बनाएगी, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी और अग्रिम क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा मज़बूत होगी।

- इस सहयोग से दूरसंचार सुविधाओं तक नागरिकों की पहुँच में वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर दिबांग घाटी और अंजॉ ज़िलों में, जहाँ अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अक्सर संचार व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करके, यह परियोजना इन दूरस्थ ज़िलों को डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास की मुख्यधारा में एकीकृत करने में मदद करेगी।

Key Points:-

(i) कनेक्टिविटी के अलावा, यह साझेदारी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोबाइल नेटवर्क तक बेहतर पहुँच आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को बढ़ावा देगी। यह इन संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों

और स्थानीय निवासियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करके सीमाओं की अधिक प्रभावी सुरक्षा में भी मदद करेगी।

(ii) भारती एयरटेल के साथ भारतीय सेना की साझेदारी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा और समावेशी विकास दोनों को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम को दर्शाती है।

(iii) इन दुर्गम इलाकों में मोबाइल संचार में सुधार करके, यह पहल सैनिकों के लिए एक मजबूत संचार आधार सुनिश्चित करती है, साथ ही सीमावर्ती आबादी के लिए डिजिटल सशक्तिकरण भी प्रदान करती है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने FSSAI के CEO के रूप में रजित पुन्हानी को मंजूरी दी।



अगस्त 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वरिष्ठ आईएस अधिकारी रजित पुन्हानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। यह नियुक्ति कई मंत्रालयों और विभागों में शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में बड़े फेरबदल के तहत हुई है।

- बिहार कैडर के 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस) अधिकारी रजित पुन्हानी को

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 31 अगस्त 2025 को गंजी कमला वी. राव के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे।

- अपनी नई नियुक्ति से पहले, रजित पुन्हानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) में सचिव के पद पर कार्यरत थे। MSDE में उनका कार्यकाल भारत के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने और उद्योग-सम्बंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए प्रमुख सुधारों से चिह्नित था।

- एसीसी द्वारा अनुमोदित फेरबदल में अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिज़ोरम-केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर की 1991 बैच की आईएस अधिकारी देबाश्री मुखर्जी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर रजित पुन्हानी का स्थान लेंगी।

Key Points:-

(i) एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी वी एल कांता राव की हुई। उन्हें जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWRGR) में सचिव नियुक्त किया गया है।

(ii) नागालैंड कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी पीयूष गोयल को भी इस फेरबदल में शामिल किया गया है। उन्हें खान मंत्रालय (MoM) का सचिव नियुक्त किया गया है, जो भारत के खनिज अन्वेषण, खनन क्षेत्र में सुधार और संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(iii) नौकरशाही में व्यापक फेरबदल भारत सरकार के प्रमुख नियामक एवं विकासात्मक क्षेत्रों में प्रशासनिक निरंतरता, दक्षता और नेतृत्व पर केंद्रित रुख को दर्शाता है। इन नियुक्तियों से खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास, जल संसाधन और खनन जैसे क्षेत्रों में

शासन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो भारत के विकास पथ के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2. अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया।



हाल ही में, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पूर्व सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व जोड़ है।

- मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अनीश दयाल सिंह को हाल ही में डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक (DG) के रूप में अपने विशिष्ट कार्यकाल के बाद, वे दिसंबर 2024 में सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

- अनीश दयाल सिंह भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में लगभग तीन दशकों का अनुभव रखते हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में व्यापक रूप से काम किया है और बाद में भारत के दो प्रमुख अर्धसैनिक बलों का नेतृत्व भी किया है। उनकी विशेषज्ञता आतंकवाद विरोधी अभियानों और नक्सल विरोधी रणनीतियों तक फैली हुई है।

Key Points:-

(i) अपनी नई भूमिका में, अनीश दयाल सिंह महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा मामलों को संभालेंगे— जिसमें जम्मू-कश्मीर के अशांत क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्र और पूर्वोत्तर में उग्रवाद शामिल हैं। वह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे।

(ii) CRPF महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अनीश दयाल सिंह ने 36 से अधिक अग्रिम परिचालन ठिकानों का शुभारंभ किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चार नई बटालियन जोड़ीं। उन्होंने तैनाती की दूरी कम करने, सैन्य कल्याण और दक्षता में सुधार के लिए 130 बटालियनों का पुनर्गठन किया। उन्होंने 2024 के लोकसभा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा अभियानों का भी निरीक्षण किया।

(iii) अनीश दयाल सिंह, NSA अजीत डोभाल के अधीन डिप्टी चीफ रणनीतिक टीम में शामिल होंगे, जिसमें पूर्व रॉ प्रमुख राजिंदर खन्ना, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी टीवी रविचंद्रन और पूर्व राजनयिक पवन कपूर शामिल हैं। उनकी नियुक्ति भारत की सुरक्षा नीतियों को आकार देने में अनुभवी कानून प्रवर्तन नेतृत्व को अपनाने पर निरंतर जोर देने का संकेत देती है।

SPORTS

1. ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता।



अगस्त 2025 में, भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान के श्यामकेंट में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (3P) स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस ओलंपिक के बाद महत्वपूर्ण वापसी की।

• ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में 462.5 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, उन्होंने चीन के झाओ वेन्यू को मामूली अंतर से हराया, जिन्होंने 462.0 स्कोर किया, जबकि जापान के नाओया ओकाडा ने कांस्य पदक जीता।

• उन्होंने क्वालिफिकेशन चरण से ही दबदबा बनाए रखा और घुटने टेकने, लेटने और खड़े होने की पोजीशन में कुल मिलाकर 584 अंक हासिल किए। फाइनल में भी उनकी शानदार बढ़त जारी रही, और 14वें शॉट पर निर्णायक 10.8 के स्कोर के साथ उनकी बढ़त पहुँच से बाहर हो गई।

Key Points:-

(i) यह जीत 2023 में उनके पहले खिताब के बाद एशियाई चैंपियनशिप में उनका दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण है। यह पहले की रजत और कांस्य उपलब्धियों के साथ उनकी पदक तालिका में जुड़ता है, जो महाद्वीपीय मंच पर उनकी निरंतरता को रेखांकित करता है।

(ii) यह जीत उनके चुनौतीपूर्ण पेरिस ओलंपिक प्रदर्शन के बाद एक शक्तिशाली वापसी है, जो भारत के अग्रणी राइफल निशानेबाजों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करती है और उनकी मानसिक दृढ़ता और तकनीकी सटीकता का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

(iii) तोमर की जीत ने निशानेबाजी में भारत के प्रभावशाली पदकों में योगदान दिया है, जिससे महाद्वीपीय स्तर पर इस खेल में भारत का दबदबा और मजबूत हुआ है। उनकी इस उपलब्धि ने राष्ट्रीय निशानेबाजी जगत में नई ऊर्जा भर दी है और भावी प्रतिभाओं को प्रेरित किया है।

AWARDS

1. PFA अवार्ड्स 2025: मोहम्मद सलाह और मैरियोना कैल्लेन्ते को प्लेयर्स ऑफ़ द ईयर चुना गया।



मैनचेस्टर में 2025 प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन (PFA) पुरस्कारों में, लिवरपूल के मोहम्मद सलाह ने पुरुष खिलाड़ी ऑफ़ द ईयर का खिताब जीता - जो पहली बार तीन बार विजेता बने - जबकि आर्सेनल की नवागंतुक मैरियोना कैल्लेन्ते को शानदार डेब्यू सीज़न के बाद महिला खिलाड़ी ऑफ़ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया।

● मोहम्मद सलाह ने तीसरी बार PFA मेन्स प्लेयर ऑफ़ द ईयर जीतकर इतिहास रच दिया - पुरस्कार के इतिहास में पहली बार - एक उत्कृष्ट 2024-25 सीज़न के बाद जिसमें उन्होंने 29 प्रीमियर लीग गोल और 18 सहायता दर्ज की, जिससे लिवरपूल को खिताब मिला।

● आर्सेनल के साथ अपने पहले सीज़न में, स्पेन की मैरियोना कैल्लेन्ते ने महिला खिलाड़ी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 19 गोल दागे और क्लब को चैंपियंस लीग जीतने में मदद की, साथ ही फाइनल में अपनी पूर्व टीम बार्सिलोना को हराकर 18 साल के यूरोपीय खिताब के सूखे को समाप्त किया।

Key Points:-

(i) एस्टन विला के मॉर्गन रोजर्स को एक शानदार सीज़न के बाद पुरुषों का यंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर का पुरस्कार मिला, जबकि आर्सेनल की ओलिविया स्मिथ को लिवरपूल से विश्व-रिकॉर्ड ट्रांसफर के बाद महिलाओं का यंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर चुना गया। बर्नले के जेम्स ट्रेफर्ड चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ़ द ईयर जीतने वाले पहले गोलकीपर बने।

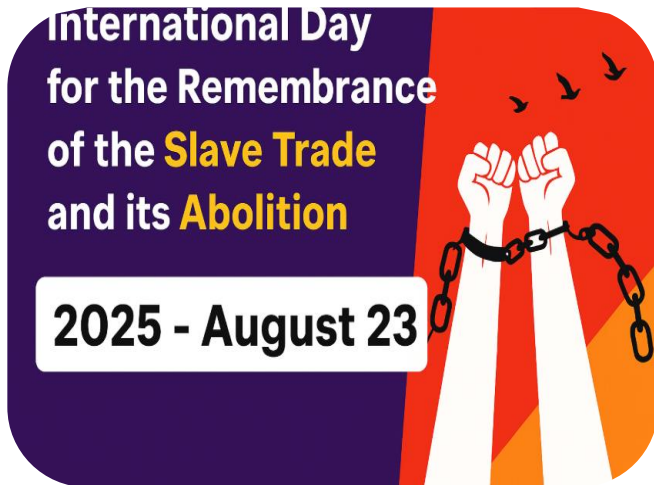
(ii) लिवरपूल का दबदबा जारी रहा और चार खिलाड़ियों—सलाह, वर्जिल वैन डाइक, रयान ग्रेवेनबेर्च और एलेक्सिस मैक एलिस्टर—को नए खिलाड़ी मिलोस केर्केज़ के साथ पीएफए मेन्स टीम ऑफ़ द ईयर चुना गया। आर्सेनल के डिफेंडर विलियम सालिबा, गेब्रियल मैगलहेस और मिडफील्डर डेक्लन राइस को भी प्रीमियर लीग टीम ऑफ़ द ईयर में जगह मिली।

(iii) (ii) लिवरपूल का दबदबा जारी रहा और चार खिलाड़ियों—सलाह, वर्जिल वैन डाइक, रयान ग्रेवेनबेर्च और एलेक्सिस मैक एलिस्टर—को नए खिलाड़ी मिलोस केर्केज़ के साथ पीएफए मेन्स टीम ऑफ़ द ईयर चुना गया। आर्सेनल के डिफेंडर विलियम सालिबा, गेब्रियल मैगलहेस और मिडफील्डर

डेक्लन राइस को भी प्रीमियर लीग टीम ऑफ़ द ईयर में जगह मिली।

IMPORTANT DAYS

1. दास व्यापार एवं उन्मूलन स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025, 23 अगस्त को मनाया गया।



संयुक्त राष्ट्र (UN) हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। यह दिन उन लाखों लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान ट्रांसाटलान्टिक दास व्यापार के कारण कष्ट सहे थे।

- इस वार्षिक समारोह का समन्वय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा किया जाता है, जो दास व्यापार के इतिहास को संरक्षित करने और इसके उन्मूलन संघर्षों को उजागर करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है।

- इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा 1997 में यूनेस्को महासम्मेलन के 29वें सत्र के दौरान की गई थी, जब संकल्प 29 सी/40 द्वारा आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था।

Key Points:-

(i) इसके बाद, 29 जुलाई 1998 को, UNESCO के महानिदेशक ने परिपत्र CL/3494 जारी कर सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों को इस दिवस के पालन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। पहला आधिकारिक स्मरणोत्सव 23 अगस्त 1998 को हैती में आयोजित किया गया था।

(ii) 23 अगस्त का चयन प्रतीकात्मक है, यह 23 अगस्त 1791 की रात को चिह्नित करता है जब सेंट-डोमिंगु (आधुनिक हैती और डोमिनिकन गणराज्य) में गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों ने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, जो अंततः ट्रांसाटलान्टिक दास व्यापार के उन्मूलन की दिशा में वैश्विक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया।

(iii) यह दिवस गुलाम लोगों के संघर्ष और प्रतिरोध की याद दिलाता है, तथा नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव और गुलामी के आधुनिक रूपों से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

OBITUARY

1. वरिष्ठ CPI नेता और पूर्व सांसद सुरवरम सुधाकर रेड्डी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया।



22 अगस्त 2025 को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुरवरम सुधाकर रेड्डी का 83 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में निधन हो

गया। 25 मार्च 1942 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य (अब तेलंगाना) के महबूबनगर जिले के कोंड्रावपल्ली गाँव में जन्मे, उन्हें उनके दशकों लंबे राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया गया।

- सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने अपना सार्वजनिक जीवन एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया, जहां 1970 में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) के अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर वे प्रमुखता से उभरे। उनके शुरुआती नेतृत्व ने युवाओं और शैक्षिक सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया, जिससे मुख्यधारा की राजनीति में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- अपने संसदीय जीवन में, सुधाकर रेड्डी ने 1998 और 2004 दोनों बार CPI सांसद के रूप में तेलंगाना के नलगोंडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने सक्रिय रूप से श्रम अधिकारों और कल्याण का समर्थन किया, और संसद में हाशिए के समुदायों की जरूरतों को आवाज देने के लिए मान्यता प्राप्त की।

Key Points:-

(i) श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों, कार्यस्थल सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल की विशेषता संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के हितों के अनुरूप श्रम नीतियों को बनाने के निरंतर प्रयास थे।

(ii) CPI के भीतर सुधाकर रेड्डी का नेतृत्व सबसे प्रमुख तब हुआ जब उन्हें 2012 में पार्टी का महासचिव चुना गया। उन्हें दो बार फिर से चुना गया, 2015 में पुडुचेरी में और 2018 में कोल्लम, केरल में, जो पार्टी के राष्ट्रीय ढांचे के भीतर उनके प्रभाव और स्वीकृति को रेखांकित करता है।

(iii) हालाँकि उनका नेतृत्व कार्यकाल 2021 तक

जारी रहने वाला था, लेकिन सुधाकर रेड्डी ने स्वास्थ्य कारणों से 2019 में स्वेच्छा से पद छोड़ दिया। उनके जाने से भाकपा के एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा मज़दूर अधिकारों, युवा सशक्तिकरण और समाजवादी मूल्यों के प्रति समर्पण का एक अमिट उदाहरण बनी हुई है।

Static GK

Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
Andhra Pradesh	मुख्यमंत्री: एन. चंद्रबाबू नायडू	राज्यपाल: एस. अब्दुल नज़ीर
Indian Army	थल सेनाध्यक्ष (COAS): जनरल उपेंद्र द्विवेदी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Thailand	मुद्रा: थाई बाट	आधिकारिक भाषा: थाई
Professional Footballers' Association (PFA)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : महेता मोलांगो	मुख्यालय : मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम (UK)
Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI)	स्थापना : 2008	मुख्यालय: नई दिल्ली
Appointments Committee of the Cabinet (ACC)	स्थापना: 1950	मुख्यालय: नई दिल्ली
Tripura	मुख्यमंत्री: माणिक साहा	राज्यपाल: एन. इंद्रसेना रेड्डी

Maharashtra	मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस	राज्यपाल: सी. पी. राधाकृष्णन
--------------------	------------------------------------	---------------------------------